



संपादकीय

ਕਈ ਫਾਇਲਾਂ ਔਰਾਂ ਚੇਹਦੇ ਹੋਂਗੇ ਬੇਨਕਾਬ

जब सच से सामना होता है, तब सबकी बोलती बंद हो जाती है। कुछ इसी प्रकार का वातावरण फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर भी हो सहा है। इस फिल्म का एक तरफ विरोध भी हो रहा है, लेकिन जिसने इस दर्द को झेला है, उसने जब इस फिल्म को देखा तो उसकी आंखों के समक्ष गुजरे हुए दर्दनाक पल आते चले गए। जिन लोगों ने यह झेला है उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। धर्मान्तरपेक्षका का ढोंग करने वाले कथित बुद्धिजीवी वर्ग का जिस प्रकार से नैरेटिव ध्वनि होता हुआ दिखाई दे सहा है, उससे उनके पेट में मरोड़ उठ रही है। उनका कहना है कि फिल्म का एक ही पक्ष दिखाया गया है, लेकिन कश्मीर घाटी का बड़ा सच यही है कि केवल हिन्दुओं को ही अपने घर और व्यवसाय से बेदखल किया गया। इसी प्रकार कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि यह सब पाकिस्तान के संरक्षण में कार्य करने वाले आतंकवादियों के संकेत पर ही हो रहा था। जहां तक बॉलीवुड की बात है तो यह सच है कि कई फिल्मों में हिन्दू देवी-देवताओं का पत्थर की मूर्ति कहकर संबोधित किया गया है, जबकि ऐसी टिप्पणियां अन्य धर्मों के आगाधक पर किया जाए तो भूचाल आ जाता है। वास्तविकता यह है कि फिल्मों के माध्यम से भारतीय नागरिकों का ब्रेन बॉश किया गया और हमारा समाज भी उसे इसलिए स्वीकार करता गया क्योंकि वह सत्य से बहुत दूर जा चुका था। अब जब सच सामने आ रहा है तो सबकी आंखों पर जो परदा चढ़ा था, वह हटने लगा है। दर्द केवल उन्हीं को हो रहा है, जिन्होंने इस आवरण को चढ़ाने का कार्य किया था। विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स सही मायनों में एक फिल्म ही नहीं, बल्कि एक ऐसा सच है जिसे हिन्दुस्तान ने झेला है। कश्मीरी हिन्दुओं के दर्द पर बर्नी फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर आज देशभर में चर्चा हो रही है। फिल्म के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री से एक पत्रकार ने पूछा कि वह अगली फिल्म किस मुद्दे पर बनाने की सोच रहे हैं तो उनका जवाब था कि उनकी अगली फिल्म दिल्ली दंगों पर होगी। यानी अब नैरेटिव रिवर्सल का दौर शुरू हो चुका है। अब अति संवेदनशील कहे जाते रहे मुद्दों को भी छूने का साहस बॉलीवुड में आने लगा है। ऐसी साहसिक फिल्मों पर तर्क-वितर्क होने लगे हैं। राजनीति से लेकर सामाजिक रूपरेखा पर सवाल उठने लगे हैं और यह जरूरी भी है और समय की मांग भी। अब ये सवाल जरूर पूछे जाने चाहिए कि हमारी सरकार के सामने कश्मीर में (या कहीं पर भी) ऐसी क्या मजबूरी होती है जिसकी वजह से आरा मशीन में लकड़ी की तरह एक महिला को चार देने का अधिकार दे दिया जाता है? ऐसा कौन सा इंकलाब होता है जिसमें ऐलान करके बहू-बेटियों के साथ सामूहिक तुर्कम होता है। उनकी नृशंस हत्या होती है या फिर ऐसी कौन-सी मजबूरी होती है, जिसकी वजह से आतंक से लाल होती धरती को देखकर भी दिल्ली दरबार को आंखे मूँद लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है? देश की हर पार्टी और हर काल के नेतृत्व को बताना चाहिए कि दुनिया में ऐसा कौन-सा अभागा देश है या अभागी जनता है जो एक करिल को दिल्ली दरबार में समान पाते देखती है। जेकिएलाएफ के नेता यासीन मलिक से हाथ मिलाते पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तस्वीर देखकर तब भी देश की जनता दांत पीसकर रह गई थी। इस पाक परस्त नेता ने पूरी ठसक के साथ कैमरे के सामने स्वीकार किया था कि उसने भारतीय वायुसेना के चार निहत्ये अधिकारियों को भरे चौराहे पर गोलियों से भून दिया।

निम्नल रानो

इससे पूर्व 2017 में ही
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद
के कार्यकाल में क्रिसमस
पर होने वाली केरोल
सिंगिंग का आयोजन भी
रद्द कर दिया गया था।
इसी प्रकार प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री
निवास में न तो कभी
इफ्तार पार्टी की मेजबानी
की और न ही किसी
इफ्तार पार्टी में शामिल
हुए। प्रधानमंत्री मोदी को
देखकर उनकी पार्टी के
अनेक नेता, मंत्री
मुख्यमंत्रियों ने इफ्तार
पार्टियों से दूरी बनाना
शुरू कर दिया।

तुष्टीकरण की राजनीति और सद्भाव का संदेश

निम्नल रानी

इससे पूर्व 2017 में ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के कार्यकाल में क्रिसमस पर होने वाली कैरोल सिंगिंग का आयोजन भी रद्द कर दिया गया था। इसी प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री निवास में न तो कभी इफ्टार पार्टी की मेजबारी की और न ही किसी इफ्टार पार्टी में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी को देखकर उनकी पार्टी के अनेक नेता, मंत्री मुख्यमंत्रियों ने इफ्टार पार्टियों से दूरी बनाना शुरू कर दिया

पिछली गैर भाजपाई सरकारों पर अल्पसंख्यकों खासकर मुस्लिमों का तुष्टीकरण करने का आरोप लगाते रहे हैं। और इसी दृष्टिकोण की बौद्धलत देश के बहुसंख्य हिन्दू समाज को अपने पक्ष में गोलबद्द करने का काम भाजपा दशकों से करती रही है। मिसाल के तौर यदि यूपी पीए सरकार के दौर में हज पर जाने वाले यात्रियों को सब्सिडी दी जाती थी तो उसे यह तुष्टीकरण बताते थे। कोई राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री यदि ख्वाजा मुर्ईनुदीन चिश्ती की अजमेर शरीफ स्थित दरगाह अथवा किसी अन्य पीर फकीर की दरगाह पर सद्व्वावना के तहत अपनी ओर से मजार पर चढ़ाने के लिये चादर भेजता था तो वह भी इनकी 'परिभाषा' के अनुसार तुष्टीकरण था। मदरसों को प्रोत्साहित करने हेतु बनने वाली योजनाएं 'तुष्टीकरण' यहाँ तक कि रमजान के दिनों में यदि कहाँ राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या कोई मंत्री रोजा इन्स्टार का आयोजन करता था तो उसे भी 'तुष्टीकरण' ही बताया जाता था। यह और बात है कि इसी 'तथाकथित तुष्टीकरण काल' के दौरान ही जस्टिस राजेंद्र सच्चर की अल्पसंख्यकों की स्थिति के बारे में आई रिपोर्ट भारतीय मुसलमानों की आर्थिक, सामाजिक व शैक्षिक स्थिति का जो खुलासा करती है वह मुस्लिम 'तुष्टीकरण' जैसे आरोपों से बिलकुल विपरीत थी। बहरहाल 'तुष्टीकरण' के आरोपों की इसी नाव पर सवार होकर भाजपा ने 2014 में केंद्र की सत्ता संभाली। बहुसंख्यक वाद की राजनीति कर देश के बहुसंख्यक हिन्दूओं को यह जताने का प्रयास किया कि मादी सरकार हिन्दू हितों का सम्मान व ध्यान रखने वाली एक ऐसी सरकार है जिसमें अब 'मुस्लिम तुष्टीकरण' की कोई गुंजाइश नहीं है। केंद्र की मादी सरकार का ऐसा ही एक निर्णय था जनवरी 2018 में मुसलमानों को हज यात्रा के लिए दी जाने वाली सब्सिडी खत्म करने का फैसला लिया जाना। हालांकि सरकार द्वारा हज के अतिरिक्त दूसरी धार्मिक यात्राओं जैसे कैलाश मानसरोवर व ननकाना साहिब गुरुद्वारा की यात्रा के लिए भी सरकार की ओर से सब्सिडी दी जाती रही है। जबकि मुसलमानों की ओर से किसी भी नेता, दल अथवा संगठन ने हज यात्रा के लिये सब्सिडी दिये जाने की मांग कभी नहीं की। बल्कि ठीक इसके विपरीत मुसलमानों का एक बड़ा तबका,



अनेक मुस्लिम धार्मिक संस्थाएं तथा मुस्लिम हितों की बात करने वाले असदुद्दीन औवैसी जैसे सांसद भी हज सब्सिडी को खत्म करने की मांग करते रहे। इन्हीं हालात में साल 2012 में ही सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र को वर्ष 2022 तक चरणबद्ध तरीके से हज सब्सिडी खत्म करने का निर्देश भी दिया था। परन्तु मोदी सरकार ने 2018 में ही हज सब्सिडी समाप्त कर इसे मुस्लिम अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण समाप्त करने के अपने एजेंडे के रूप में दर्शाया। उस समय सरकार की ओर से यह भी बताया गया कि हज सब्सिडी समाप्त करने के सरकार के फैसले से 700 करोड़ रुपये बचेंगे और ये पैसे अल्पसंख्यकों की शिक्षा विशेषकर मुस्लिम लड़कियों की शिक्षा पर खर्च किये जायेंगे। इसी तरह देश में रमजान महीने में नेताओं द्वारा इफ्तार पार्टी दिये जाने की काफी पुरानी परंपरा है। देश में हिन्दू-मुस्लिम-सिख-ईसाई भाईचारे तहत यह सिलसिला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बांटवारे के कुछ समय बाद ही शुरू किया था। उस समय कांग्रेस के तत्कालीन पार्टी कार्यालय 7 जंतर मंतर पर पंडित नेहरू इफ्तार पार्टी दिया करते थे। हालांकि 1965 में भारत-पाकिस्तान युद्ध के बाद इफ्तार पार्टी का यह सिलसिला कुछ वर्षों तक थम गया था। परन्तु 1971 के भारत-पाकिस्तान-बांग्लादेश युद्ध में पाकिस्तान की ऐतिहासिक पराजय के पश्चात तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1972 में दिल्ली में एक बहुत बड़ा ईद मिलन समारोह आयोजित किया था। इसमें जयप्रकाश नारायण सहित पूरे देश के पक्ष विपक्ष के

अनेक बड़े नेता व राजदूत शरीक हुए थे। इंदिरा गांधी के शासनकाल में इफ्टार पार्टी ही नहीं बल्कि होली-दीवाली मिलन, गुरु पर्व मिलन, क्रिसमस मिलन भी आयोजित होता रहा। देश में साप्रदायिक सद्ग्राव को बढ़ावा देने गरज से पूरे राष्ट्रपति भवन व प्रधानमंत्री निवास से लैकर देश के अनेक केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री के आवास व अनेक पार्टी मुख्यालयों पर इफ्टार पार्टीयां हुआ करती थीं। परन्तु 25 जुलाई, 2017 को जब रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली उसी समय उन्होंने यह निर्णय लिया कि - 'राष्ट्रपति भवन एक सार्वजनिक इमारत है, यहां सरकार या कर दाताओं के पैसों से किसी भी धार्मिक त्योहार का आयोजन नहीं होगा। और राष्ट्रपति के इस फैसले के साथ ही राष्ट्रपति भवन में स्वतंत्रता के बाद से चली आ रही इफ्टार पार्टी की परंपरा समाप्त हो गयी।

इससे पूर्व 2017 में ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के कार्यकाल में क्रिसमस पर होने वाली कैरोल सिंगिंग का आयोजन भी रह कर दिया गया था। इसी प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री निवास में न तो कभी इफ्टार पार्टी की मेजबानी की और न ही किसी इफ्टार पार्टी में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी को देखकर उनकी पार्टी के अनेक नेता, मंत्री मुख्यमंत्रियों ने इफ्टार पार्टीयों से दूरी बनाना शुरू कर दिया। इन सब बातों का एक ही सन्देश था कि भाजपा मुस्लिम तुष्टीकरण का कोई काम नहीं करती। परन्तु पिछली सरकारों पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाने वाली भाजपा सरकार तथा भाजपा के मातृ

भी वृद्धि गयी है। इसी तरह रोजा इफ्टार को मुस्लिम तुष्टीकरण बताने वाले लोगों विशेषकर आर एस एस द्वारा इन दिनों चल रहे रमजान के दिनों में देश के इतिहास में पहली बार इफ्टार पा की कई छोटी बड़ी दावतें देने की घोषणा की गयी है। जानकारों का मानना है कि मुसलमानों तक अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए संघ ने यह योजना बनाई है। खबरों के अनुसार एक महीने चलने वाले रमजान के प्रारंभिक बीस दिनों में आंध्र प्रदेश व तेलंगाना राज्यों में रोजा इफ्टार की कई दावतें आयोजित की जायेंगी। इतना ही नहीं बल्कि रमजान माह के अंतिमी 10 दिनों में ईद मिलन समारोह का सिलसिला भी चलेगा। संघ के अधीन संचालित होने वाले संगठन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संरक्षक डॉ इंद्रेश कुमार का मत है कि - 'हम सभी एक साथ तभी तरक्की कर सकते हैं यदि हम नफरत को दफ्न कर दें। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि हम सांप्रदायिक सद्ग्राव को और बढ़ाएं।' डॉ इंद्रेश कुमार के अनुसार -'

इस रमजान से हम एक नई शुरूआत करने जा रहे हैं। परन्तु सरकार की मुस्लिम हितकारी योजनाओं और आर एस एस के इफ्टार पार्टीयों के आयोजन से यह सवाल जरूर खड़ा होता है कि जब पिछली सरकारों में यही अथवा इस तरह के निर्णय होते थे तो यही आज के 'सद्ग्राव के तथाकथित ध्वजबाहक' उन फैसलों को मुस्लिम तुष्टीकरण बताते थे? अखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि यदि यही काम वह करें तो तुष्टीकरण और यह करें तो सद्ग्राव?

रेलवे के सुरक्षा प्रबंधों पर लगातार सवाल उठ रहे

पिछले करीब तीन महीने से ए

और एक श्रमिक महिला ने रेल पटरी के बीचों-बीच अपनी लाल साड़ी दिखाकर चालक को सचेत किया। 28 मार्च को छतीसगढ़ के जामगांव रेलवे स्टेशन के निकट एक ही पटरी पर दो मालागाड़ियां आ जाने से उनकी टक्कर हो गई। 5 मार्च को सहारनपुर से दिल्ली आ रही पैसेंजर ट्रेन में अचानक आग लगने से यात्रियों में हड्डकंप मच गया था। उससे पहले बिहार के मधुबनी रेलवे स्टेशन पर खड़ी स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस की कुछ बोगियों में 19 फरवरी की सुबह एकाएक आग लग गई थी। लापरवाही के चलते लगातार हो रहे ऐसे रेल हादसों की बहुत लंबी फैहरित है लेकिन चिंता की बात यह है कि लगातार होते ऐसे हादसों से कोई सबक नहीं लिया जाते। जब भी बड़ा रेल हादसा होता है तो रेलवे द्वारा भविष्य में ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कड़े कदम उठाने का रटा-रटाया जवाब सुनने को मिलता है लेकिन थोड़े ही समय बाद जब फिर कोई रेल हादसा सामने आता है तो रेल तंत्र के ऐसे दावों की कलई खुल जाती है। ऐसे रेल हादसों के बाद प्रायः जांच के नाम पर कुछ रेल कर्मचारियों व अधिकारियों पर गाज

लोग मारे गए, जिनमें पटीरी से उत्तरने वाली ट्रैकों ने ही 347 जाने ली। रेलवे सेफटी और यात्री सुरक्षा से जुड़े एक सवाल के जवाब में संसद में बताया गया था कि रेल हादसों की बड़ी वजह रेलवे स्टाफ की नाकामी, सड़क पर चलने वाली गाड़ियां, मशीनों की खराबी और तोड़-फोड़ रही। 2014-15 के 135 रेल हादसों में 60, 2015-16 में हुए 107 हादसों में 55 और 2016-17 में 30 नवम्बर 2016 तक के 85 हादसों में से 56 दुर्घटनाएं रेलवे स्टाफ की नाकामी या लापरवाही के चलते हुईं। तत्कालीन रेलमंत्री सुरेश प्रभु द्वारा 2016-17 के रेल बजट में रेल दुर्घटनाएं रोकने के लिए मिशन जीरो एक्सीडेंट नामक एक विशेष अभियान शुरू करने की घोषणा की गई थी, जिसके बाद रेल दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए त्वरित पटरी नवीनीकरण, अल्ट्रासेनिक रेल पहचान प्रणाली तथा प्राथमिकता के आधार पर मानवराहित रेलवे क्रॉसिंग खत्म किए जाने जैसे विभिन्न सुरक्षा उपायों पर कार्य शुरू किया गया था किन्तु ये कार्य बहुत धीमी गति से जारी हैं।

अपारपक्ष आर कमजार प्रधानमंत्रा साबित हुए इमरान

संजीव ठाकुर

नान अब तक के पाकिस्तान के सबसे अपरिपक्व और कमजोर प्रधानमंत्री साबित हैं। कुर्सी का लालच और सत्ता के मोह ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के मानसिक संतुलन बिगाड़ दिया है। वहां पर नेशनल बली में डिप्टी स्पीकर ने इमरान सरकार साथ मिलकर विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव खारिज कर घनघोर अलोकतात्रिक निर्णय लिया है। इसी तरह इमरान खान ने संसद को कर चुनाव कराने की राष्ट्रपति को लाइश ने भी पाकिस्तान में कमजोर, निर्बल बचे कुचे लोकतंत्र को धाराशाही कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस विधाय के खिलाफ खुद संज्ञान लेकर फैसला लिया है की डिप्टी स्पीकर को अविश्वास लाव को खारिज करने का संवैधानिक अधिकार ही नहीं है, इस तरह इस पर निर्णय के लिए अपने निर्णय को 1 दिन के लिए दिया है। स्वतंत्रता के बाद से ही चुने हुए प्रधानमंत्रियों में आखरी प्रधानमंत्री इमरान नान अब तक के सर्वाधिक कमजोर और अफल प्रधानमंत्री साबित हुए हैं। उनके काल में बेरोजगारी चरम सीमा पर है, अपश्यक वस्तुओं की कीमतों में आग लगी है आम जनता की पहुंच से शक्कर, चीनी, गण, चावल बाहर हो चुका है। महांगई नवाधिक 70% ऊंचाई पर पहुंच गई है।

चीन और अरब देशों से अरबों रुपए उधारी लेकर पाकिस्तान अपनी सरकार चला रहे थे, वे अब चीन के आर्थिक रूप से गुलाम बन चुके हैं। एक घटना ने यह साबित कर दिया है कि यह घटना पाकिस्तान के संसदीय इतिहास में अभूतपूर्व है, और संभवतः भविष्य में भी ऐसा प्रकरण देखने में नहीं आएगा। विपक्ष के शहबाज नवाज, बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज, तथा विपक्ष के अन्य कदावर नेता फजलुर रहमान पाकिस्तान की आवाम और मीडिया के साथ मिलकर इमरान सरकार को धाराशाही कराने के लिए पूरी तरह कटिबद्ध हो गए हैं। इमरान खान संसद को भंग करने के बाद 3 माह के भीतर चुनाव करना करवाने की रणनीति के तहत अनेक वाले चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। पर दूसरी तरफ पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि 3 माह के भीतर चुनाव कराया जाना किसी भी तरह से संभव नहीं है चुनाव कराने के लिए कम से कम 6 माह का समय चाहिए। गैरततलब है कि पंजाब, इस्लामाबाद, बलूचिस्तान में एवं एक अन्य प्रांत में अभी स्थानीय चुनाव भी होने वाले हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मामले में इमरान सरकार और चुनाव आयोग के बीच पूर्व में ही तनातनी रही है, इस तरह चुनाव आयोग इमरान सरकार के खिलाफ जाकर 3 माह के भीतर चुनाव कराने से मना कर रहा है। इससे इमरान के अधिकारी और बढ़ जाएगी। सब यह उठता है की इमरान की खुद की पत्रहरीक ए इस्लाम के कुछ खास सिपहसाल जो इमरान के काफी नजदीक माने जाते हैं अब इमरान की हरकतों के सामने उन आलोचना कर काफी मुश्ख हो गए हैं। पंजाब सरकार के पूर्व गवर्नर चौधरी सरवर बरिष्ठ नेता कलीम खान बगावत पर उत्तर दिया है, तथा इमरान की पार्टी के मजबूत स्तंभ तक उनके खजांची जहांगीर तरेब अब पार्टी के अलग होकर नया रुख अखिलायर करने में जुट है, यह तीनों व्यक्ति काफी शक्तिशाली दमदार हैं पार्टी को कमजोर करने और तोड़ने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती राजनीतिक विशेषकों का कहना है पीटीआई 1 साल के भीतर बिखर जाएगी तथा यदि चुनाव हुए तो इमरान की पार्टी को सीटों से ज्यादा में विजय प्राप्त नहीं हो सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अनेक फैसले से यदि पूर्व मैं लिए गए इमरान सरकार के फैसले के विरोध में निर्णय आता है तो विपक्ष सरकार बनाने में सक्षम हो जाएगी तथा इमरान सरकार को विपक्ष में बैठना पड़ सकता है जिसके फलस्वरूप इमरान की मुश्खियों तक बढ़ जाएंगी। इमरान का और परिपक्वता निर्णय उन्हीं पर भारी पड़ सकता है।

विचार

अपारपक्ष आर कमजार प्रधानमंत्रा साबित हुए झमरान
सीट और अपने दोस्रे से अपने साथ चलायी जाने से एक साथ है। जाने

ब तक के पाकिस्त

अपरिपक्व और कमज़ोर प्रधानमंत्री साबित हुए हैं। कुर्सी का लालच और सत्ता के मोह ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के मानसिक संतुलन को बिगाड़ दिया है। वहां पर नेशनल असेंबली में डिप्टी स्पीकर ने इमरान सरकार के साथ मिलकर विषय के अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर घनघोर अलोकतात्त्विक निर्णय लिया है। इसी तरह इमरान खान ने संसद को भंग कर चुनाव करने की राष्ट्रपति को सिफारिश ने भी पाकिस्तान में कमज़ोर, निर्बल और बचे कुचे लोकतंत्र को धाराशाही कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस निर्णय के खिलाफ खुद संज्ञान लेकर फैसला दिया है की डिप्टी स्पीकर को अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करने का सर्वाधानिक अधिकार ही नहीं है, इस तरह इस पर निर्णय देने के लिए अपने निर्णय को 1 दिन के लिए टाल दिया है। स्वतंत्रता के बाद से ही चुने हुए 18 प्रधानमंत्रियों में आखरी प्रधानमंत्री इमरान खान अब तक के सर्वाधिक कमज़ोर और असफल प्रधानमंत्री साबित हुए हैं। उनके कार्यकाल में बेरोजगारी चरम सीमा पर है, आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में आग लगी हुई है और जनता की पहुंच से शक्कर, चीनी, आटा, चावल बाहर हो चुका है। महंगाई सर्वाधिक 70% ऊंचाई पर पहुंच गई है। थे, वे अब चीन के आर्थिक रूप से गुलाम बन चुके हैं।

एक घटना ने यह साबित कर दिया है कि यह घटना पाकिस्तान के संसदीय इतिहास में अभूतपूर्व है, और संभवतः भविष्य में भी ऐसा प्रकरण देखने में नहीं आएगा। विषय के शहबाज नवाज, बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज, तथा विषय के अन्य कदावर नेता फजलुर रहमान पाकिस्तान की आवाम और मीडिया के साथ मिलकर इमरान सरकार को धाराशाही करने के लिए पूरी तरह कटिबद्ध हो गए हैं। इमरान खान संसद को भंग करने के बाद 3 माह के भीतर चुनाव करना करवाने की रणनीति के तहत आने वाले चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। पर दूसरी तरफ पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि 3 माह के भीतर चुनाव कराया जाना किसी भी तरह से संभव नहीं है चुनाव कराने के लिए कम से कम 6 माह का समय चाहिए। गौरतलब है कि पंजाब, इस्लामाबाद, बल्चिस्तान में एवं एक अन्य प्रांत में अभी स्थानीय चुनाव भी होने वाले हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मामले में इमरान सरकार और चुनाव आयोग के बीच पूर्व में ही तनातनी रही है, इस तरह चुनाव आयोग इमरान सरकार के खिलाफ जाकर 3 माह के भीतर चुनाव यह उठता है की इमरान को खुद की पार्टी तहरीक ए इस्लाम के कुछ खास सिपहसालार जो इमरान के काफी नजदीक माने जाते थे अब इमरान की हरकतों के सामने उनकी आलोचना कर काफी मुखर हो गए हैं। पंजाब सरकार के पूर्व गवर्नर चौधरी सरवर और वरिष्ठ नेता कलीम खान बगावत पर उतर आए हैं, तथा इमरान की पार्टी के मजबूत स्वंभूत तथा उनके खजांची जहांगीर तरेब अब पार्टी से अलग होकर नया रुख अखिलयार करने में लगे हुए हैं, यह तीनों व्यक्ति काफी शक्तिशाली एवं दमदार हैं पार्टी को कमज़ोर करने और तोड़ने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है राजनीतिक विक्षेपकों का कहना है की पीटीआई 1 साल के भीतर बिखर जाएगी और यदि चुनाव हुए तो इमरान की पार्टी को 25 सीटों से ज्यादा में विजय प्राप्त नहीं हो सकती है।

सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आने वाले फैसले से यदि पूर्व में लिए गए इमरान सरकार के फैसले के विरोध में निर्णय आता है तो विषय सरकार बनाने में सक्षम हो जाएगी और इमरान सरकार को विषय में बैठना पड़ेगा जिसके फलस्वरूप इमरान की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। इमरान का और परिपक्वता भरा निर्णय उन्हीं पर भारी पड़ सकता है।

पढ़ी-लिखी युवा पीढ़ी कृषि क्षेत्र में ला रही बदलाव

रातन्द्र कवर शखावत
कोरोना काल ने ग्रामीण भारत के

को कृषि की और मोड़ दिया है। इस दौरान पढ़ी-लिखी युवा पीढ़ी कृषि क्षेत्र में आने वाली समस्याओं व इसकी दक्षता में सुधार के तरीके ढूँढ रही है। ध्यातव्य है कि हरित क्रांति (1960) से लेकर विभिन्न गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों तक, भारत कृषि प्रौद्योगिकी में लगातार विकास कर रहा है। हालांकि, भारतीय किसानों में से केवल एक टिहाई ने उन्नत प्रौद्योगिकी अपनाई है। शेष कृषि नवाचारों और खेती के आधुनिक तरीकों से अवगत नहीं हैं जो उच्च फसल पैदावार और गुणवत्ता का कारण बन सकते हैं। अगर देश में कृषि की प्रगति की बात करें तो भारत घरेलू और वैश्विक कृषि उत्पादन मांग में अग्रणी योगदानकर्ताओं में से एक है। भारत दुनिया में दृढ़ का सबसे बड़ा उत्पादक फसल और महीनी का दम्पा

सबस बड़ा उत्पादक है, साथ ही दश में लगभग 9 करोड़ किसान हैं और 45 करोड़ परिवार कृषि से जुड़े हैं। परन्तु फिर भी भारतीय कृषि व किसान कई प्रकार की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं जैसे उत्पादन में कमी, भूमि उर्वरता का क्षय, कृषि लागतों का बढ़ना, मांग व आपूर्ति असंतुलन व भारतीय कृषि का आत्मनिर्भर न होना आदि। गौरतलब है कि भारतीय कृषि मानसून पर निर्भर है व कृषि में तकनीक का उपयोग सीमित है जिससे भौमिक प्रभावों का सटीक आंकलन नहीं हो पाता जिससे भूमि के बार बार उपयोग से मृदा स्वास्थ्य का क्षय होता है। जिससे खाद्यान्मों की गुणवत्ता पर असर पड़ता है। साथ ही कृषि राज्य सूची का विषय है जिस कारण कृषिगत डेटा हर राज्य का अलग अलग है व इसमें एकरूपता का अभाव है जैसे भूमि प्राप्त की विधियां अलग हैं जलवाय

दा का गुणवत्ता , कृषि लागता
नन आदि राज्यवार अलग -
जिसके कारण एक राष्ट्रीय
नीति निर्माण में बाधा उत्पन्न
इसलिए कृषि में उत्पादन,
रखरखाव व आपूर्ति यानी
ता में मूलभूत परिवर्तनों की
जिसका समाधान तकनीकी
से सम्भव हो सकता है। अगर
तो चौपाल जैसे आईसीटी क्षेत्र
आपूर्ति श्रृंखला प्रणाली का एक
है जो किसानों को समय पर
गेक जानकारी के साथ सशक्त
। ताकि वे अपने निवेश पर
नाभ प्राप्त कर सकें। भू-
के रख-रखाव जैसे क्षेत्रों में
खाबी को दूर करने और सही
का आश्वासन देने का एक
है। आधार से जुड़े बैंक खाते
परी विकार्याएँ मारी गए जन्मपत्र क्षमता
करके माद्राक लाभा तक पहुच प्रदान
करते हैं, बदले में ऋण की पहुंच के
समस्या को हल करते हैं। इ-कॉमर्स और
एम-कॉमर्स प्लेटफार्मों के माध्यम से डोरी
कनेक्टिविटी के लिए प्रत्यक्ष खेत ने
बिचौलियों की हिस्सेदारी में कटौती करते
और उनकी उपज का उचित मूल्य प्राप्त
करने के लिए बड़ी संख्या में कारोगारों को
सुविधा प्रदान की है। गौरतलब है कि
सरकार द्वारा अपनाये गए परंपरागत
साधनों जैसे कि एमएसपी पर खरीद व
भंडारण की सुविधा , उर्वरक साइबिडी
डीबीटी आदि में समस्याएं देखने के
मिलती हैं जैसे एमएसपी का लाभ सर्वे
किसानों व सभी फसलों को न मिलकर
मुख्यतः गेहू व चावल पर ही केंद्रित है
साथ ही भण्डारण सुविधा के अभाव में
फसल बर्बाद होती है , ऐसे में सरकार
द्वारा परम्परागत नीतिगत प्रयासों के
अनिवार्य नहीं हैं तकनीकी को भी कमी

क्षत्र म उपयोग करन का राडमप
किया है । ई- तकनीक के द्वारा
उत्पादकता , खाद्य सुक्ष्मा , खाद्य गुण
, भंडारण नियंत्रित आदि के
आवश्यक परिवर्तन किए गए है ।
तकनीक से यहां अर्थ है आई सं
, बिग डेटा , स्प्रेस तकनीक ,
सेसिंग , ड्रोन , जी आई एस, ब्लॉविं
आदि का इसेमाल कृषि उत्पाद
बढ़ाने व उसे उन्नत करने के
जना । इन सभी से सरकार के
कृषिगत विकास के लिए जो प
आंकड़ों का अभाव है उसे दूर किय
सकेगा । यहाँ बात करें तो सरकार
2015 में जारी डिजिटल इण्डिया प
के तहत ई क्रॉप्ट कार्यक्रम चलाया ग
जिसमें किसानों के लिए तकनीक
उपयोग जैसे ऑनलाइन ऋण, बै
सुविधा, बीज, खाद्य खरीद आदि शा
किया गा ।

नवेन्दु उमेष

बाजार में पेट्रोल बहुत इतरा रहा था। उसे इतराता हुआ सोने-चांदी और शेयर को देखा नहीं गया। इस पर सोना उसकी ओर मुखातिब होते हुए बोला-आखिर क्या बात है कि तुम बाजार में आज बहुत इतरा रहे हो। जबाब में पेट्रोल बोला-देख नहीं रहे हो मैंने अपनी कीमत बढ़ाकर बाजार में आग लगा दिया है। अगे पेट्रोल ने कहा-देश के लोग अच्छे दिन अनेका इत्तजार कर रहे थे लेकिन उनके तो अच्छे दिन आये नहीं, अब हमारे अच्छे दिन आ गये हैं। इसी लिए आज मैं इतरा रहा हूं। सोना-चांदी और शेयर के घमंड तोड़ते हुए पेट्रोल ने कहा एक समय था तुमलोगों की खबरें प्रतिदिन अखबार के प्रथम पृष्ठ पर प्रकाशित होती थीं-सोना गिरा और चांदी टूट। इसी प्रकार शेयर के भाव चढ़े और बढ़े। लेकिन अब तुमलोग खबरों से गायब हो चुके हो। तुम्हारे चढ़ने और गिरने से समाज में कई फर्क नहीं पड़ रहा है। इनदिनों खबरों में मेरा डंका बज रहा है। चौक-चौपड़े पर स्वतंत्र-सत्रांग चारों के साथ मिर्ग मेरी ही चर्चा लोग कर रहे हैं। इससे जाहिर होता है मैं कितना बलसाती हूं।

पेट्रोल का प्रवचन चल ही रहा था कि कछ मीडिया वाले वहां आ धमके और बताने लगे कि पन्द्रह दिनों में पेट्रोल-डीजल की कीमत में काफी उछाल आया है। वे यह भी बताने लगे कि आगे आने वाला समय और भी कठिन है। पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि से इनकार नहीं किया जा सकता। मीडियाकार्मियों की बातों को सुनकर पेट्रोल ने कहा-मेरा मार्केट वैल्यू बढ़ने से मेरा सीना छतीस इंच से बढ़कर छप्पन इंच हो गया है। अब वह दिन दूर नहीं जब लोग अपना वाहन लेकर नहीं दावात लेकर पेट्रोल पंप पर जायेंगे और पेट्रोल पंप वाले से कहेंगे मुझे एक दावात पेट्रोल देना। वह दिन भी दूर नहीं जब दूल्हा दहेज में अपने होने वाले ससरु से बाइक के साथ-साथ आजीवन पेट्रोल की मांग करेगा। अगर ससरु पेट्रोल देने में अक्षम होगा तो दूल्हा अपनी नई नवेली दूल्हन को लेकर जायेगा और पेट्रोल पंप के दर्शन करा करके अपने घर वापस लौट जायेगा।

विदेश संदेश

चीन के शंघाई में अभिभावकों को कोरोना संक्रमित बच्चों के साथ रहने की अनुमति

बीजिंग। चीन के शंघाई शहर में अभिभावकों को कोरोना वायरस से संक्रमित अपने बच्चों के साथ रहने की अनुमति दे दी गई है। शहर के स्वास्थ्य अधिकारी के शीर्ष निरीक्षक वू गैन्यू ने ऐसा किया कि वे माता-पिता जो स्वास्थ्य जीवितों से पूरी तरह से अवगत हैं और समझते हैं कि एक हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हैं, उन्हें अब बच्चों के साथ निरागानी केंद्रों में रहने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि, गैन्यू ने पत्रकारों से कहा कि माता-पिता के लिए मास्क पहनना और अलग होकर भोजन करना अनिवार्य रहेगा। साथ ही उन्हें अन्य कोविड-19 नियमों का भी सख्ती से पालन करना होगा।



18 साल से छोटे यूजर्स में लोकप्रिय जुए के विज्ञापन नहीं कर सकेंगे सेलिब्रिटी

लंदन। बिटेन ने ऐसे जुए के विज्ञापनों पर रोक लगा दी है, जो 18 से कम उम्र के यूजर्स के बीच लोकप्रिय हैं और जिनमें कई सेलिब्रिटी दिखाए जा रहे हैं। यहां के विज्ञापन मानक प्रधिकरण (एपए) ने नए सख्त नियम जारी किए हैं जो अक्सर से लाग जाते हैं। इनमें कहा गया कि युवाओं और कमज़ोर दर्शकों को जुए की लत से सुरक्षा देने की ज़रूरत है। जुए के विज्ञापनों का गहरा प्रभाव दर्शकों पर होता है। यास्तोर पर बढ़े सेलिब्रिटी, खिलाड़ी, सोशल मीडिया इफ्फूलसर आदि आगर इनमें शामिल होते हैं तो इसका लोगों को नुकसान होता है। इन सेलिब्रिटी की 18 साल से छोटे दर्शकों के दिलों पर गहरा पहुंच होती है।

रोनाल्डो भी आ चुके हैं इन विज्ञापनों में

फूटबॉल क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड के क्रिस्टाणो रोनाल्डो, चेल्सी के मैनेजर जोस मार्टिनो इम्प्रेक्टर के विज्ञापनों में नज़र आ चुके हैं। इसके खिलाफ बिटेन की विज्ञापनों पर बनी संक्रमित ने एपए को लिखा था। उन्होंने इन विज्ञापनों को नैतिक नियमों के खिलाफ बताया था। उसका कहना था कि इन्हें किशोरों व युवाओं को प्रभावित करने के लिए नहीं बनाना चाहिए।

विशेषज्ञों ने बनाया पीपुल्स सीडीसी, सरकारी संस्था डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन पर लगाए गंभीर आरोप

वाशिंगटन। अमेरिका की बहुचर्चित संस्था डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (सीडीसी) एप अंगीर आरोप लगाए गए हैं। ये अरोप खुद अमेरिका के लगभग 15 संक्रमित रोग विशेषज्ञों ने लगाए हैं। उनका इलाज है कि सीडीसी कॉर्पोरेट सेक्टर की मर्जी के मुताबिक चल रहा है। ये संस्था अपने फैसले उन कार्यालयों के मुनाफे को ध्यान में रख कर ले रही है। इन विशेषज्ञों का एक लंबा बयान बिटिश अखबार द गार्जिंग की बी-2 दुनिया के कई अमेरिकी के लिए अधिकारी ने यह भी कहा कि इन्हें चाहता है कि नवी दिल्ली रूसी सैन्य उपकरणों पर अपनी निर्भरता कम करें।

ऑस्टिन ने वार्षिक रक्षा बजट पर अमेरिकी कांग्रेस की कार्यालयी के द्वारा सन् की स्वास्थ्य सेवा संस्थित के स्वस्थों को बताया, 'हम उनके (भारत) साथ बात करके उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि रूसी उपकरणों में निवेश जारी रखना उनके हित में नहीं है। हम

पाकिस्तान एयरलाइन ने दमजान दौरान अपने चालक दल स्टाफ के दोजा रखने पर लगाया प्रतिबंध

इस्लामाबाद: पाकिस्तान इंटरेनशनल एयरलाइन्स ने अपने कैप्टन और प्रथम अधिकारियों के इस्लामी परिवार महीने रमजान के दौरान रोजा रखने पर प्रतिबंध लगा दिया है। PIA का यह फैसला कराची में दो साल पहले हुए विमान हावड़े के महेनजर आया है। इस हावड़े में चालक दल के सदस्यों समेत विमान में सवार 100 लोगों की मौत हो गई थी। विमान चालक ने उस समय रोजा रखा हुआ था।

PIA के प्रवक्ता अब्दुल्ला हफीज ने बताया कि कॉकपिट चालक दल के सदस्यों के लिए सुझा ब्लॉटिंग जारी किया गया है। उन्होंने कहा, "कॉकपिट

चालक दल के सदस्यों पर चाहते हैं, उन्हें अवकाश लेना होगा।" प्रवक्ता ने कहा कि रोजा

कियित्स्कीय कारणों से रोजे के चाहते हैं, उन्हें अवकाश लेना होगा।" प्रवक्ता ने कहा कि रोजा महीने रमजान के दौरान रोजा रखने के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकते हैं। उन्होंने कहा, "रोजा रखते हुए विमान संचालन न केवल व्यक्ति के लिए स्वयं खतरा है, बल्कि विमान में मौजूदी के लिए भी यह खतरनाक है।" इस्लामी कैलेंडर के नवी महीने रमजान के दौरान दुनियाभर के मुसलमान भारत से देखा रखते हैं। रमजान दो अप्रैल से आरंभ हुआ था और यह ईंट-उल-फितर के साथ समाप्त होगा।

चालक दल के सदस्यों पर चाहते हैं, उन्हें अवकाश लेना होगा।" प्रवक्ता ने कहा कि रोजा रखने वाले कैबिन चालक दल के दिया गया है। जो लोग रोजा रखना सदस्यों को विमान संचालन की

रखने वाले कैबिन चालक दल के दिया गया है।

चालक दल के सदस्यों पर चाहते हैं, उन्हें अवकाश लेना होगा।" प्रवक्ता ने कहा कि रोजा

कियित्स्कीय कारणों से रोजे के चाहते हैं, उन्हें अवकाश लेना होगा।" प्रवक्ता ने कहा कि रोजा

कियित्स्कीय कारणों से रोजे के चाहते हैं, उन्हें अवकाश लेना होगा।" प्रवक्ता ने कहा कि रोजा

कियित्स्कीय कारणों से रोजे के चाहते हैं, उन्हें अवकाश लेना होगा।" प्रवक्ता ने कहा कि रोजा

कियित्स्कीय कारणों से रोजे के चाहते हैं, उन्हें अवकाश लेना होगा।" प्रवक्ता ने कहा कि रोजा

कियित्स्कीय कारणों से रोजे के चाहते हैं, उन्हें अवकाश लेना होगा।" प्रवक्ता ने कहा कि रोजा

कियित्स्कीय कारणों से रोजे के चाहते हैं, उन्हें अवकाश लेना होगा।" प्रवक्ता ने कहा कि रोजा

कियित्स्कीय कारणों से रोजे के चाहते हैं, उन्हें अवकाश लेना होगा।" प्रवक्ता ने कहा कि रोजा

कियित्स्कीय कारणों से रोजे के चाहते हैं, उन्हें अवकाश लेना होगा।" प्रवक्ता ने कहा कि रोजा

कियित्स्कीय कारणों से रोजे के चाहते हैं, उन्हें अवकाश लेना होगा।" प्रवक्ता ने कहा कि रोजा

कियित्स्कीय कारणों से रोजे के चाहते हैं, उन्हें अवकाश लेना होगा।" प्रवक्ता ने कहा कि रोजा

कियित्स्कीय कारणों से रोजे के चाहते हैं, उन्हें अवकाश लेना होगा।" प्रवक्ता ने कहा कि रोजा

कियित्स्कीय कारणों से रोजे के चाहते हैं, उन्हें अवकाश लेना होगा।" प्रवक्ता ने कहा कि रोजा

कियित्स्कीय कारणों से रोजे के चाहते हैं, उन्हें अवकाश लेना होगा।" प्रवक्ता ने कहा कि रोजा

कियित्स्कीय कारणों से रोजे के चाहते हैं, उन्हें अवकाश लेना होगा।" प्रवक्ता ने कहा कि रोजा

कियित्स्कीय कारणों से रोजे के चाहते हैं, उन्हें अवकाश लेना होगा।" प्रवक्ता ने कहा कि रोजा

कियित्स्कीय कारणों से रोजे के चाहते हैं, उन्हें अवकाश लेना होगा।" प्रवक्ता ने कहा कि रोजा

कियित्स्कीय कारणों से रोजे के चाहते हैं, उन्हें अवकाश लेना होगा।" प्रवक्ता ने कहा कि रोजा

कियित्स्कीय कारणों से रोजे के चाहते हैं, उन्हें अवकाश लेना होगा।" प्रवक्ता ने कहा कि रोजा

कियित्स्कीय कारणों से रोजे के चाहते हैं, उन्हें अवकाश लेना होगा।" प्रवक्ता ने कहा कि रोजा

कियित्स्कीय कारणों से रोजे के चाहते हैं, उन्हें अवकाश लेना होगा।" प्रवक्ता ने कहा कि रोजा

कियित्स्कीय कारणों से रोजे के चाहते हैं, उन्हें अवकाश लेना होगा।" प्रवक्ता ने कहा कि रोजा

कियित्स्कीय कारणों से रोजे के चाहते हैं, उन्हें अवकाश लेना होगा।" प्रवक्ता ने कहा कि रोजा

कियित्स्कीय कारणों से रोजे के चाहते हैं, उन्हें अवकाश लेना होगा।" प्रवक्ता ने कहा कि रोजा

कियित्स्कीय कारणों से रोजे के चाहते हैं, उन्हें अवकाश लेना होगा।" प्रवक्ता ने कहा कि रोजा

कियित्स्कीय कारणों से रोजे के चाहते हैं, उन्हें अवकाश लेना होगा।" प्रवक्ता ने कहा कि रोजा

कियित्स्कीय कारणों से रोजे के चाहते हैं, उन्हें अवकाश लेना होगा।" प्रवक्ता ने कहा कि रोजा

कियित्स्कीय कारणों से रोजे के चाहते हैं, उन्हें अवकाश लेना होगा।" प्रवक्ता ने कहा कि रोजा

कियित्स्कीय कारणों से रोजे के चाहते हैं, उन्हें अवकाश लेना होगा।" प्रवक्ता ने कहा कि रोजा

कियित्स्कीय कारणों से रोजे के चाहते हैं, उन्हें अवकाश लेना होगा।" प्रवक्ता ने कहा कि रोजा

कियित्स्कीय कारणों से रोजे के